Suniye Sarker 2nd March 2026_Layout 1 3/2/2026 9:48 PM Page 1

देहरादून से प्रकाशित। साप्ताहिक समाचार पत्र | वर्षः 01, अंक 02, सोमवार, 02 मार्च 2026 | www.suniyesarkar.com | मूल्यः ₹ 5

कुछ घाव अच्छे हैं!

शिक्षा निदेशालय में पहले कुटाई, फिर बन गए काऊ नौडियाल के बड़े भाई

अजय नौटियाल (सुनिए सरकार)

देहरादून। राजधानी के शिक्षा निदेशालय में कुछ सप्ताह पहले जो हुआ, वह अब दैनिक सुर्खियों से उतर चुका है। टीवी डिबेट्स आगे बढ़ गईं।

सोशल मीडिया का गुस्सा किसी और मुद्दे की ओर मुड़ गया। सरकारी फाइलें अपनी गति से चलती रहीं। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़े हैं।

यह सिर्फ एक झड़प की कहानी नहीं थी। यह सिर्फ एक एफआईआर का मामला नहीं था। यह सिर्फ एक अधिकारी और एक जनप्रतिनिधि के बीच तनाव की घटना नहीं थी। यह उत्तराखंड में एक ऐसे सिस्टम की झलक थी जहां संवाद की जगह टकराव ने ले ली, और फिर टकराव की जगह अचानक सुलह और औपचारिक सामान्यता ने ले ली।

और इसी घटनाक्रम के बीच आया वह मोड़ जिसने पूरे प्रकरण को नया रंग दे दिया। विवाद के केंद्र में रहे अधिकारी अजय कुमार नौडियाल को सेवानिवृत्ति से ठीक दो दिन पहले पदोन्नति मिल गई।

राजनीति में टाइमिंग बहुत कुछ कहती है।

प्रशासन में टाइमिंग अक्सर 'प्रक्रिया' कहलाती है।

जनता के लिए टाइमिंग सवाल बन जाती है।

घटना का क्रम-दफ्तर हुआ गरम

घटनाक्रम की शुरुआत प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े असंतोष से हुई बताई जाती है। बताया गया कि स्थानीय स्तर पर कुछ मुद्दों को लेकर प्रतिनिधियों और विभाग के बीच मतभेद थे। तनाव बढ़ा। बातचीत तेज हुई। आरोप लगे कि भाषा की मर्यादा टूटी। एफआई आर दर्ज हुई। वीडियो क्लिप्स सामने आए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। जांच शुरू हुई। कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें भी आईं।

पहले पिटाई-कुटाई ये कैसे भाई?

उधर संबंधित जनप्रतिनिधि उमेश शर्मा 'काऊ' की ओर से यह कहा गया कि स्थिति 'गरम' हो गई थी। बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि अधिकारी अजय नौडियाल उनके 'छोटे भाई' जैसे हैं। राजनीति में यह वाक्य नया नहीं है। 'भाई जैसा' संबंध अक्सर विवाद के बाद सामने आता है। लेकिन जनता के लिए यह क्रम कुछ यूं दिखा। पहले तनाव। फिर टकराव। फिर FIR..फिर बयान। फिर भाईचारा। क्या यही राजनीतिक परिपक्वता है? या यही भारतीय लोकतांत्रिक शैली है?

और फिर मिला प्रमोशन

सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब शासन की ओर से पदोन्नति सूची जारी हुई। अजय कुमार नौडियाल को रिटायरमेंट से ठीक दो दिन पहले प्रमोशन गिफ्ट मिला।

अब यहां दो दृष्टिकोण

पहला– यह पदोन्नति नियमित प्रक्रिया का हिस्सा थी। सीनियरिटी, सेवा रिकॉर्ड और औपचारिक नियमों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। विवाद से इसका कोई संबंध नहीं। **दूसरा–** क्या यह सिर्फ संयोग था? क्या घटनाक्रम ने फाइल की गति बढ़ा दी? क्या प्रशासन ने संदेश देना चाहा?

(शेष पेज 2 पर)

सुनिए सरकार-सिस्टम से सवाल

- क्या प्रशासनिक निर्णयों की टाइमिंग पारदर्शी रूप से सार्वजनिक की जानी चाहिए?
- क्या विवाद के तुरंत बाद होने वाली पदोन्नतियां अनावश्यक शंकाएं पैदा करती हैं?
- क्या यह आवश्यक है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में राज्य सरकार स्पष्ट प्रेस नोट जारी करे?
- क्या राजनीतिक तनाव के बाद प्रशासनिक 'सामान्यता' घोषित कर देना पर्याप्त है?

टिहरी लेक फेस्टिवलः रोमांच और आध्यात्म

आगामी 6 से 9 मार्च टिहरी झील पर्यटन क्षमता का बनेगा बड़ा मंच

देहरादून/ टिहरी (सुनिए सरकार ब्यूरो)। आगामी 6 से 9 मार्च के बीच टिहरी झील एक बार फिर उत्तराखंड की पर्यटन क्षमता का बड़ा मंच बनने जा रही है। Himalayan O_2-टिहरी लेक फेस्टिवल के जरिए उत्तराखंड सरकार एडवेंचर, संस्कृति और आध्यात्म को एक साथ प्रस्तुत करने जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों उद्घाटन प्रस्तावित है। जिला प्रशासन और पर्यटन विकास परिषद इस आयोजन को बड़े स्तर पर आयोजित कर रहे हैं। ट्रैकिंग, राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग से लेकर पांडवाज और अमित त्रिवेदी जैसे कलाकारों की प्रस्तुति तक-यह आयोजन बहुआयामी है। देवप्रयाग में गंगा आरती, योग और रघुनाथ मंदिर दर्शन इस फेस्टिवल को आध्यात्मिक आयाम भी देंगे।

प्रतियोगिता और पुरस्कार

एक लाख रुपए तक के पुरस्कारों की घोषणा प्रतिभाओं को मंच देने का संकेत है। मास्टर शेफ, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया रील, मिस्टर एंड मिस टिहरी, रैप सिंगिंग जैसी प्रतियोगिताएँ युवाओं को जोड़ने का प्रयास हैं।

सुनिए सरकार-सिस्टम से सवाल

- क्या यह आयोजन केवल चार दिनों की चमक तक सीमित रहेगा, या टिहरी को सालभर पर्यटन केंद्र बनाने की ठोस योजना भी है?
- क्या स्थानीय युवाओं को केवल आयोजन के दौरान अस्थायी रोजगार मिलेगा, या स्थायी अवसरों का रोडमैप भी तैयार है
- क्या एडवेंचर गतिविधियों में सुरक्षा प्रोटोकॉल और बीमा कवर पूरी तरह सुनिश्चित है?
- क्या पर्यावरणीय संतुलन पर असर का आकलन किया गया है, ताकि झील और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहे?
- क्या फेस्टिवल के बाद भी देवप्रयाग, प्रतापनगर, घनसाली जैसे क्षेत्रों का निरंतर प्रचार होगा?

पर्यटन बनाम पर्यावरण

टिहरी झील और आसपास के पर्वतीय क्षेत्र केवल पर्यटन उत्पाद नहीं हैं-ये संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। अगर पर्यटन बढ़ता है तो कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और जल संरक्षण... (शेष पेज 2 पर)

होली से पहले चढ़ेगा पाराः 3-4 डिग्री तक बढ़ सकता है प्रदेश का तापमान

नई दिल्ली/ देहरादून (सुनिए सरकार ब्यूरो)। उत्तराखंड में मौसम अब करवट ले रहा है। फरवरी के आखिरी सप्ताह के साथ ही सर्द हवाओं की तीव्रता कम होने लगी है और धूप में तेजी आने लगी है। दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास शुरू हो गया है, जबकि सुबह और रात के समय अभी भी ठंडक बनी हुई है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, होली से पहले प्रदेश में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। साफ आसमान और शुष्क मौसम के कारण तापमान में यह बढ़ोतरी संभावित है। फिलहाल किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में नहीं दिख रहा है, जिससे बारिश की संभावना कम बनी हुई है।

देहरादून में पारा बढ़ने के संकेत

राजधानी देहरादून में 25 फरवरी के बाद अधिकतम तापमान में क्रमिक वृद्धि की

संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान भी धीरे-धीरे बढ़ते हुए 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

इसका मतलब साफ है कि सुबह और शाम हल्की ठंडक महसूस होगी, लेकिन दोपहर में धूप का असर ज्यादा रहेगा और तापमान सामान्य से अधिक महसूस हो सकता है।

मैदानी इलाकों में दोपहर के समय तेज धूप लोगों को गर्मी का एहसास कराएगी, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि जारी रहेगी। (शेष पेज 2 पर)

प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के काम की नापी रफ्तार

256 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है तैयार

लोहाघाट में निर्माणाधीन संस्थान का सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया निरीक्षण।

नई दिल्ली/ देहरादून/चंपावत (सुनिए सरकार ब्यूरो)। उत्तराखंड में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ी पहल के तहत जनपद चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र स्थित छमनिया में लगभग 256 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन प्रदेश के प्रथम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएं। निरीक्षण के दौरान फुटबॉल ग्राउंड, एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सहित विभिन्न खेल मैदानों की प्रगति की समीक्षा की गई।

साथ ही छात्रावास, प्रशासनिक भवन, अकादमिक ब्लॉक, मल्टीपर्पज हॉल, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस निर्माण कार्यों की स्थिति की भी जानकारी ली गई।

सुनिए सरकार-सिस्टम से सवाल

- क्या निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरा होगा?
- संचालन के लिए योग्य कोच और स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जाएंगे?
- क्या छात्रवृत्ति और आरक्षण नीति स्पष्ट होगी?
- क्या निर्माण गुणवत्ता की स्वतंत्र तकनीकी जांच होगी?
- क्या यह कॉलेज प्रदेश की खेल क्रांति की शुरुआत बनेगा?

निष्कर्षः नारी सशक्तिकरण की ओर अहम कदम

- 256 करोड़ की यह परियोजना केवल खेल ढांचा नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- अब निगाहें इस पर हैं कि यह संस्थान कितनी शीघ्रता और गुणवत्ता के साथ तैयार होकर प्रदेश की बेटियों के सपनों को पंख देता है।

स्पोर्ट्स कॉलेज-एक नजर में

स्थानः छमनिया, लोहाघाट (जनपद चम्पावत

कुल लागतः लगभग 256 करोड़

प्रमुख खेल सुविधाएंः फुटबॉल ग्राउंड, एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट

अवसंरचना सुविधाएंः
300 बालिकाओं की क्षमता वाला छात्रावास, प्रशासनिक भवन, अकादमिक ब्लॉक, मल्टीपर्पज हॉल, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, स्टाफ क्वार्टर

उद्देश्यः महिला खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग, ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच, प्रशिक्षण, शिक्षा व आवास की समग्र व्यवस्था

राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू

देहरादून/अजमेर (सुनिए सरकार ब्यूरो)। पीएम मोदी ने राजस्थान के अजमेर से 14 वर्षीय लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इसे गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर के खिलाफ भारत की लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब परिवार में मां स्वस्थ रहती है, तो परिवार हर संकट का सामना कर सकता है। इसी भावना से महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं।''

क्यों जरूरी है यह अभियान?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की 2022 ग्लोबोकैन रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1.2 लाख से अधिक नए सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें से लगभग 80 हजार मौतें हो जाती हैं। महिलाओं में यह दूसरा सबसे आम कैंसर उच्च जोखिम वाले एचपीवी प्रकार (16 और 18) इस कैंसर के प्रमुख कारण माने जाते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, एचपीवी वैक्सीन 93-100 फीसदी तक प्रभावी है, उन प्रकारों के खिलाफ जिन पर इसका दायरा सीमित है।

दुनिया में 194 में से 160 देशों ने राष्ट्रीय कार्यक्रम में एचपीवी टीका शामिल किया है। 90 देशों ने एकल खुराक मॉडल अपनाया है। भारत भी वैश्विक वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुरूप गार्डसिल-4 का उपयोग कर रहा है

सुनिए सरकार सिस्टम से सवाल

- क्या ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक अभियान की पहुंच समान रूप से सुनिश्चित होगी?
- क्या अभिभावकों को जागरूक करने के लिए पर्याप्त जनजागरण अभियान चलाया जाएगा?
- क्या स्कूल आधारित समन्वय प्रणाली मजबूत की गई है?
- क्या टीकाकरण के बाद निगरानी और एईएफआई प्रबंधन की व्यवस्था हर जिले में सुदृढ़ है?
- क्या भविष्य में 15झ18 आयु वर्ग को भी चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा?
- क्या यह पहल भारत की बेटियों को कैंसर-मुक्त भविष्य की ओर ले जाएगी?

निष्कर्ष

- एचपीवी टीकाकरण अभियान भारत की निवारक स्वास्थ्य नीति में एक बड़ा कदम है।
- यह केवल एक टीका नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य की दीर्घकालिक सुरक्षा का प्रयास है।
- अब चुनौती यह है कि यह अभियान कागज़ों से निकलकर हर गांव, हर कस्बे, हर परिवार तक पहुंचे।

(पेज 1 की शेष खबरें...)

...कुछ घाव अच्छे हैं! शिक्षा निदेशालय में

सरकार ने इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया। लेकिन सार्वजनिक विमर्श में सवाल बने रहे।

राजनीति के रंग और होली का मौसमः होली का मौसम है। यह त्योहार रंगों का है। गिले-शिकवे मिटाने का है। लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर कहते हैं कि ''बुरा न मानो होली है।'' लेकिन क्या शासन-प्रशासन में भी यही लागू होता है?

पहले रंग गहरा। फिर पानी से धुला। फिर मुस्कान।

एक पुराना विज्ञापन याद आता हैः ''दाग अच्छे हैं।'' पर शासन में हर दाग अच्छा नहीं होता। हर घाव सीख नहीं देता। कुछ घाव यह याद दिलाते हैं कि सिस्टम को अभी और मजबूत होना है।

प्रशासन बनाम राजनीतिः संतुलन कहाँ? भारतीय लोकतंत्र की संरचना में जनप्रतिनिधि और अफसर दोनों महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जनप्रतिनिधि जनता की आवाज हैं। अफसर प्रशासनिक ढांचे के संरक्षक हैं। जब दोनों में सामंजस्य होता है, तब नीतियां लागू होती हैं। जब दोनों में टकराव होता है, तब फाइलें रुकती हैं।

वातावरण गरम होता है। और अंततः जनता प्रभावित होती है।

इस प्रकरण ने यही दिखाया कि संवाद तंत्र कितना मजबूत है? क्या औपचारिक बैठकें पर्याप्त हैं? क्या विवाद समाधान की कोई स्पष्ट प्रणाली है?

शिक्षक और कर्मचारी संगठनों की भूमिकाः इस घटनाक्रम के बाद शिक्षक संगठनों और कर्मचारी संघों ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। कई स्थानों पर विरोध स्वर सुनाई दिए। सुरक्षा की मांग उठी। यह भी लोकतंत्र का हिस्सा है।

लेकिन यहाँ भी वही सवाल कि क्या आंदोलन की भाषा संयमित थी?

क्या संवाद के रास्ते खुले थे?

क्या दोनों पक्षों ने समय रहते बात करने की कोशिश की?

क्या प्रमोशन संदेश था?ः कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पदोन्नति का निर्णय एक संदेश हो सकता है कि अधिकारी का मनोबल गिरने नहीं दिया जाएगा।

दूसरे मानते हैं कि यह केवल सेवा नियमों का पालन था। जबकि तीसरे कहते हैं कि सिस्टम अक्सर विवाद के बाद संतुलन बनाने की कोशिश करता है।

सवाल यह नहीं कि निर्णय सही था या गलत। सवाल यह है कि क्या निर्णय की पारदर्शिता पर्याप्त थी?

आईना-गलती कहाँ होती है?ः सच यह है कि टकराव कभी एकतरफा नहीं होता। अफसरों की 'मैं सिस्टम हूं' वाली सोच कभी-कभी संवाद के दरवाजे बंद कर देती है। जनप्रतिनिधियों की 'मैं जनता की आवाज हूं' वाली तीव्रता मर्यादा की सीमाएं धुंधली कर देती है, और कर्मचारी संगठनों का गुस्सा मांगों की वैधता को भावनाओं में डुबो देता है। जब तीनों पक्ष अपनी-अपनी जगह अडिग रहते हैं, तब टकराव अपरिहार्य हो जाता है।

निष्कर्षः इस पूरे घटनाक्रम से तीन स्पष्ट सीख निकलती हैं। संवाद ही समाधान है। दफ्तर तार्किक बहस व विचार-विमर्श की जगह हैं, अखाड़ा नहीं।

टाइमिंग पारदर्शी होनी चाहिएः

प्रशासनिक निर्णय जितने स्पष्ट होंगे, शंकाएं उतनी कम होंगी। जवाबदेही संबंधों से ऊपर है। भाईचारा अच्छी बात है, पर लोकतंत्र में पहले जवाबदेही आती है।

होली का त्योहार हमें सिखाता हैः रंग मिलते हैं तो सुंदरता बनती है। पर अगर रंग गंदे हों तो चेहरा धुंधला हो जाता है। लोकतंत्र में भी यही नियम है। कुछ घाव अच्छे हो सकते हैं। अगर वे सुधार की दिशा दिखाएं, लेकिन अगर घाव को रंग से ढक दिया जाए, तो वह केवल कहानी बनकर रह जाता है।

जैसी व्यवस्थाएं भी उसी अनुपात में मजबूत होनी चाहिए।

...टिहरी लेक फेस्टिवलः रोमांच और आध्यात्म

स्थानीय अर्थव्यवस्था को अवसरः ऐसे आयोजनों से होमस्टे, होटल, टैक्सी, लोक कलाकार, हस्तशिल्प और फूड वेंडर्स को लाभ मिलता है। सवाल यह है कि क्या यह लाभ कुछ दिनों तक सीमित रहेगा? या इसे नीति के स्तर पर स्थायी पर्यटन मॉडल में बदला जाएगा?

होली से पहले रंगः होली से पहले यह फेस्टिवल रंगों का उत्सव भी है। लेकिन ''बुरा न मानो होली है'' प्रशासनिक मॉडल नहीं हो सकता। योजनाएं रंगीन हों, पर जवाबदेही पारदर्शी होनी चाहिए।

निष्कर्षः टिहरी लेक फेस्टिवल उत्तराखंड की संभावनाओं का प्रतीक है। रोमांच, संस्कृति और आध्यात्म का यह संगम स्वागत योग्य है। लेकिन हर बड़े आयोजन के साथ बड़ा प्रश्न भी आता है कि क्या हम इसे दीर्घकालिक विकास की रणनीति बना पाएंगे?

...होली से पहले चढ़ेगा पारा

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश में शुष्क मौसम बना रहेगा। तेज धूप के कारण दोपहर में गर्माहट बढ़ेगी, लेकिन रात का तापमान अभी भी राहत देगा। मौसम के इस संक्रमण काल में शरीर को बदलते तापमान के अनुरूप ढालना जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य पर बरतें सावधानी

✓ दिन में तेज धूप से बचाव के लिए हल्के सूती कपड़े पहनें
✓ पानी का सेवन बढ़ाएँ
✓ सुबह-शाम की ठंडक को ध्यान में रखते हुए परतदार कपड़े पहनें
✓ बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें

सुनिए सरकार-सिस्टम से सवाल

- क्या बदलते मौसम को देखते हुए स्कूलों के समय में समायोजन पर विचार होगा?
- क्या स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों को लेकर कोई डवाइजरी जारी की है?
- क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट किया गया है?

निष्कर्ष

होली से पहले मौसम रंग बदल रहा है।
दिन में गर्मी का संकेत है,
रात में अब भी राहत है।
मौसम का यह बदलाव साफ बताता है कि सर्दी की विदाई और गर्मी की आहट शुरू हो चुकी है।
होली इस बार रंगों के साथ गर्माहट भी लेकर आएगी।

Suniye Sarker 2nd March 2026_Layout 1 3/2/2026 9:48 PM Page 3

गरम होगी सियासत, बर्फीली वादियों में उठेंगे तीखे सवाल

राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आगामी 9 मार्च से बजट सत्र शुरू

देहरादून/ गैरसैंण-भराड़ीसैंण (सुनिए सरकार ब्यूरो)। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आगामी 9 मार्च से शुरू होने जा रहा विधानसभा का बजट सत्र इस बार राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और संभावित रूप से हंगामेदार रहने वाला है।

पहाड़ की शांत वादियों के बीच होने वाला यह सत्र सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक का मंच बन सकता है।

सत्ता पक्ष ही पूछ रहा सबसे ज्यादा सवाल: इस बार की सबसे दिलचस्प स्थिति यह है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से अधिक सवाल खुद सत्ता पक्ष भाजपा के विधायकों ने लगाए हैं।

प्रश्नकाल की सूची के अनुसार भाजपा विधायक अपनी ही सरकार से जवाब मांगने में आगे नजर आ रहे हैं। यह संकेत देता है कि सत्ता पक्ष के भीतर भी स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर दबाव बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति दोहरे उद्देश्य- "क्षेत्रीय जनता के मुद्दों को सीधे सरकार के सामने रखना और विपक्ष के संभावित हमलों की धार को पहले ही कुंद करना" हो सकती है।

कांग्रेस आर-पार के मूड में: दूसरी ओर, प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बार सदन के भीतर और बाहर धामी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। विपक्ष ने सरकार की कथित विफलताओं को सूचीबद्ध करते हुए एक विस्तृत चार्जशीट तैयार की है।

कांग्रेस का मुख्य फोकस: बढ़ती महंगाई, रसोई गैस व खाद्य सामग्री की कीमतों में वृद्धि, युवाओं में बढ़ता असंतोष, रोजगार के घटते अवसर, हालिया भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं के आरोप कांग्रेस का मुख्य फोकस रहने वाले हैं।

विपक्षी नेताओं का कहना है कि धामी सरकार जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है, जबकि बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है।

8 मार्च को तय होगा एजेंडा: विधानसभा सचिवालय के अनुसार, 8 मार्च को गैरसैंण में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सत्र का औपचारिक एजेंडा तय होगा। उसी दिन विपक्ष भी अपने विधानमंडल दल की बैठक कर सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को अंतिम रूप देगा। संकेत मिल रहे हैं कि यदि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा टाली गई, तो सत्र के पहले दिन ही गतिरोध की स्थिति बन सकती है।

पहले दिन ही बजट पेश होने की संभावना: धामी सरकार राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद ही वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो यह राज्य के विधायी इतिहास में दूसरा अवसर होगा। इससे पहले मार्च 2022 में भी राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन ही लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था। इस कदम को धामी सरकार की आक्रामक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, ताकि विपक्ष को शुरुआती बढ़त न मिले।

भाजपा का पलटवार: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने पिछले 4 वर्षों में केवल हंगामा किया है और जनहित के मुद्दों से उनका कोई स-रोकार नहीं रहा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विपक्ष का रुख नकारात्मक रहा, तो आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में उसका राजनीतिक नुकसान तय है। भट्ट ने कांग्रेस को सत्र में सार्थक चर्चा में भाग लेने की नसीहत दी है।

मुद्दे जो गरमाएंगे सदन: प्रदेश की आर्थिक स्थिति, पर्यटन और चारधाम यात्रा की तैयारियां, युवाओं के लिए रोजगार नीति, शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति, गैरसैंण का प्रतीकात्मक महत्व, ग्रामीण विकास और पलायन आदि मुद्दे छाए रहने वाले हैं। गैरसैंण केवल एक स्थान नहीं, बल्कि राज्य आंदोलन की भावनाओं का प्रतीक है। यहां होने वाला हर सत्र राजनीतिक संदेश देता है। ऐसे में यह बजट सत्र केवल वित्तीय दस्तावेज भर नहीं रहेगा, बल्कि 2027 के चुनावी समीकरणों की भी गणित होगा।

सुनिए सरकार-सिस्टम से सवाल

- गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का दर्जा और सम्मान कब मिलेगा?
- क्या विधानसभा में इस विषय पर औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा?
- कब तक हम अस्थायी राजधानी देहरादून से ही काम चलाते रहेंगे?
- क्या राजधानी स्थानांतरण के लिए चरणबद्ध प्रशासनिक योजना तैयार है?
- क्या पर्वतीय क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए राजधानी परिवर्तन जरूरी नहीं?
- क्या गैरसैंण में पूर्ण सचिवालय, विभागीय ढांचा और स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने की ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक की जाएगी?
- क्या बजट सत्र के दौरान सरकार इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करेगी?

सुनिए सरकार गैरसैंण पर सवाल

- क्या बजट में युवाओं के लिए ठोस रोजगार रोडमैप आएगा या केवल घोषणाएं होंगी?
- क्या सरकार के पास कोई स्पष्ट रोडमैप, बजट आवंटन और समयसीमा है?
- भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या नई व्यवस्था लाएगी?
- महंगाई से राहत के लिए राज्य स्तर पर क्या ठोस कदम प्रस्तावित हैं?
- गैरसैंण में सत्र आयोजित करने के प्रतीकात्मक निर्णय को क्या स्थायी संस्थागत मजबूती मिलेगी?
- क्या सदन संवाद का मंच बनेगा या फिर एक बार फिर शोर-शराबे में जनता के मुद्दे दब जाएंगे?
- क्या विधानसभा में इस विषय पर औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा?

मिडिल ईस्ट में जंग की आहट, उत्तराखंड के घरों में बेचैनी

देहरादून/रुड़की/हरिद्वार (सुनिए सरकार ब्यूरो)। मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य तनाव अब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सुर्खी नहीं रहा।

इसका असर उत्तराखंड के उन घरों तक पहुंच चुका है, जहां बेटे, भाई और पति खाड़ी देशों में काम या पढ़ाई कर रहे हैं। बहरीन, अबू धाबी, कतर और आसपास के इलाकों से लगातार धमाकों, सायरन और सुरक्षा अलर्ट की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में यहां उत्तराखंड में बैठे परिवारों की रातें बेचैनी में गुजर रही हैं।

"आसमान में आग थी...हम बच्चे लेकर भागे": रुड़की मूल के एक युवक, जो दो दशक से अधिक समय से बहरीन में रह रहे हैं, ने बीते शनिवार को अपने परिचित को फोन पर बताया कि अचानक तेज धमाकों की आवाजें आने लगीं।

कुछ ही मिनटों में हालात अफरा-तफरी में बदल गए। उनके अनुसार, रिहायशी इलाके के पास कई विस्फोट हुए, जिससे लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे।

उन्होंने पत्नी और बच्चों को लेकर इलाके से निकलने की कोशिश की। धुएं के गुबार, ट्रैफिक जाम और पेट्रोल पंपों पर लंबी कता-रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि माहौल सामान्य नहीं है और हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है।

सुनिए सरकार सिस्टम से सवाल

- क्या राज्य सरकार खाड़ी देशों में रह रहे उत्तराखंड के नागरिकों का आधिकारिक डेटा तैयार करेगी?
- क्या आपातकालीन संपर्क केंद्र बनाया जाएगा?
- क्या संकट की स्थिति में तत्काल वापसी की स्पष्ट रणनीति है?
- क्या विदेश में काम कर रहे श्रमिकों के लिए बीमा और सुरक्षा तंत्र की समीक्षा होगी?

अबू धाबी से वीडियो कॉल: "बाहर निकलना मना है": हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार को उनके रिश्तेदार ने अबू धाबी से वीडियो कॉल पर बताया कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। पास के क्षेत्र में धमाके की आवाज सुनाई देने के बाद सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया। कमरे के भीतर बैठे परिवार के सदस्य लगातार समाचार चैनल देख रहे हैं और स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं।

हजारों उत्तराखंडी खाड़ी देशों में: उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में कार्यरत हैं।

होटल, निर्माण, सुरक्षा, तेल उद्योग और स्वास्थ्य सेवाओं में हजारों युवक काम कर रहे हैं। कुछ छात्र भी उच्च शिक्षा के लिए इन देशों में रह रहे हैं। तनाव बढ़ने के बाद यहां उनके परिवार लगातार संपर्क साधने की कोशिश में जुटे हैं।

जिनका फोन लग गया, वे राहत में हैं। जिनका नहीं लग पा रहा, वहां चिंता बढ़ती जा रही है।

चारधाम यात्रा 2026: 6 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू, कोई शुल्क नहीं

देहरादून (सुनिए सरकार ब्यूरो)। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा-2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू होगी। गढ़वाल आयुक्त आईएएस विनय शंकर पांडेय ने बताया कि पहले चरण में केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रहेगी, जबकि यात्रा शुरू होने के बाद ऑफलाइन काउंटर भी खोले जाएंगे।

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने स्पष्ट किया कि इस बार पंजीकरण पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "श्रद्धालुओं की सुविधा और पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है।

पंजीकरण का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है, न कि राजस्व संग्रह।" चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बदरीनाथ धाम 23 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम परंपरागत रूप से अक्षय तृतीया (19 अप्रैल) को खुलते हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा शीघ्र होगी।

सुनिए सरकार-सिस्टम से सवाल

- क्या इस बार रजिस्ट्रेशन पोर्टल बिना तकनीकी समस्या के चलेगा?
- क्या यात्रा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित और गड्ढामुक्त होंगे?
- क्या आपदा की स्थिति में रेस्क्यू तंत्र पर्याप्त और तत्पर रहेगा?
- आस्था का सफर शुरू होने से पहले तैयारियों की परीक्षा अब सिस्टम की है।

Suniye Sarker 2nd March 2026_Layout 1 3/2/2026 9:48 PM Page 4

संपादक की कलम से

अजय नौटियाल
प्रधान संपादक, सुनिए सरकार

'सुनिए सरकारः एक अखबार नहीं, एक संवाद'

जब मैंने 'सुनिए सरकार' शुरू करने का फैसला लिया तो सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा गया कि आज के डिजिटल दौर में अखबार क्यों। जब हर हाथ में मोबाइल है तो कागज पर छपने की जरूरत क्या है। लेकिन सच यह है कि सूचना की अधिकता के इस समय में सुनवाई कम हो गई है। खबरें तेज हैं, लेकिन गहराई कम है। बयान बहुत हैं, लेकिन जवाब कम हैं। इसी कमी ने 'सुनिए सरकार' को जन्म दिया।

अखबार सिर्फ कागज नहीं होता, वह समय का दस्तावेज होता है। सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं और कुछ घंटों में गायब हो जाती हैं, लेकिन अखबार सवाल को स्थायी बनाता है। वह दर्ज करता है कि किसने क्या कहा, कब कहा और उसके बाद क्या हुआ। मैंने पत्रकारिता में यह महसूस किया कि उद्घाटन और घोषणाएं तो छपती हैं, लेकिन उनका असर नहीं। योजनाओं की तस्वीरें छपती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कम दिखती है। धीरे धीरे बिना पूछे आगे बढ़ जाने की आदत बन जाती है। 'सुनिए सरकार' उसी आदत के खिलाफ एक छोटा प्रयास है।

यह अखबार किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं है। यह मौन के खिलाफ है। जब जनता चुप हो जाती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। जब सिस्टम सुनना बंद कर देता है तो अविश्वास बढ़ता है। हमारा उद्देश्य टकराव नहीं, संवाद है। हमारा उद्देश्य विरोध नहीं, जवाबदेही है। लोकतंत्र सिर्फ पांच साल में एक बार वोट देने का नाम नहीं है। लोकतंत्र रोज का अभ्यास है। किसान अपनी समस्या कह सके, छात्र परीक्षा पर सवाल उठा सके, महिला अपनी असुरक्षा व्यक्त कर सके और पत्रकार बिना डर के सवाल पूछ सके झ यही लोकतंत्र की असली ताकत है।

आज सबसे बड़ी समस्या सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी नहीं, बल्कि भरोसे का संकट है। युवा मेहनत करता है लेकिन उसे परिणाम पर भरोसा नहीं होता। भर्ती निकलती है तो परीक्षा टल जाती है, रिजल्ट आता है तो विवाद हो जाता है। युवा को सिर्फ नौकरी नहीं, पारदर्शिता चाहिए। उसे यह विश्वास चाहिए कि सिस्टम निष्पक्ष है। अगर भरोसा टूटेगा तो गुस्सा बढ़ेगा, और गुस्सा बढ़ेगा तो समाज में दूरी बढ़ेगी।

महिला सुरक्षा भी हमारे समाज की परीक्षा है। कानून जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। सुरक्षा संवेदनशील माहौल से आती है। घर में सम्मान, स्कूल में सही शिक्षा, सड़क पर सुरक्षा और कार्यस्थल पर बराबरी झ ये चार आधार मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा। नारी शक्ति का मतलब सिर्फ मंच पर सम्मान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सम्मान है।

मीडिया की भूमिका भी आज पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मीडिया को तय करना होगा कि वह सनसनी चुनेगा या संतुलन। 'सुनिए सरकार' कोशिश करेगा कि खबर को तथ्य के साथ रखा जाए। सवाल होंगे, लेकिन बिना पूर्वाग्रह के। हम हर सप्ताह एक बड़ा सवाल उठाने, एक योजना का जमीनी असर जांचने और एक सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम व्यवस्था को गिराने नहीं, सुधारने की दिशा में काम करना चाहते हैं।

यह अखबार मेरे लिए व्यवसाय नहीं, जिम्मेदारी है। हर शब्द सोच समझकर छापना होगा। सवाल पूछना आसान नहीं होता, लेकिन सुधार की शुरुआत सवालों से ही होती है। अगर जवाबदेही तय होगी तो भरोसा लौटेगा। अगर संवाद बढ़ेगा तो दूरी घटेगी।

'सुनिए सरकार' एक अपील है- सरकार से कि सुनिए, जनता से कि बोलिए और सिस्टम से कि जवाब दीजिए। अगर हम संवाद की संस्कृति बना पाए तो लोकतंत्र मजबूत होगा। यह अखबार उसी विश्वास की तलाश है।

डिजिटल युग और सूचना की विश्वसनीयता का बढ़ता संकट

जवाबदेही विशेष (सुनिए सरकार)

आईएएस बंशीधर तिवारी
सूचना महानिदेशक और अपर सचिव-मुख्यमंत्री

हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब सूचना बिजली की गति से चलती है। सुबह की एक घटना दोपहर तक देश भर में वायरल हो जाती है और शाम तक उस पर हजारों प्रतिक्रियाएं, विश्लेषण और बहसें खड़ी हो जाती हैं। मोबाइल फोन आज सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं रहा, वह निजी न्यूजरूम बन चुका है। हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है। हर व्यक्ति के पास मंच है, और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रसारक बन चुका है। डिजिटल क्रांति ने सूचना को लोकतांत्रिक बनाया है।

पहले खबरें चुनिंदा संस्थानों से आती थीं, अब कोई भी व्यक्ति वीडियो, पोस्ट या ट्वीट के माध्यम से सूचना साझा कर सकता है। यह बदलाव सकारात्मक भी है। इससे आवाजों को मंच मिला, स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय पहचान मिली, और कई बार प्रशासनिक तंत्र को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन इसी के साथ एक गंभीर संकट भी खड़ा हुआ है- विश्वसनीयता का संकट।

आज सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि सूचना उपलब्ध है या नहीं। चुनौती यह है कि सही सूचना कौन सी है? सोशल मीडिया पर चलने वाली हर खबर सत्य नहीं होती। कई बार अधूरी जानकारी, पुराने वीडियो या संदर्भ से हटाए गए बयान वायरल होकर भ्रम पैदा कर देते हैं।

लोग बिना सत्यापन के संदेश आगे बढ़ा देते हैं। परिणाम यह होता है कि अफवाहें वास्तविकता से तेज दौड़ने लगती हैं। फेक न्यूज केवल गलत सूचना नहीं है। यह सामाजिक विश्वास को भी कमजोर करती है। जब समाज में बार-बार भ्रम फैलता है, तो लोग किसी भी स्रोत पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। लोकतंत्र का आधार ही सूचना पर टिका है। यदि नागरिकों को सही तथ्य न मिलें, तो निर्णय भी भ्रमित होंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म की संरचना भी इस समस्या को बढ़ाती है।

एल्गोरिदम अक्सर उसी सामग्री को आगे बढ़ाते हैं जो ज्यादा प्रतिक्रिया पैदा करे। सनसनी, आक्रोश और विवाद तेजी से फैलते हैं, जबकि संतुलित और विश्लेषणात्मक सामग्री पीछे रह जाती है। क्लिक, व्यू और लाइक की दौड़ ने कई बार गहराई को सतहीपन से बदल दिया है।

यहां मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पारंपरिक पत्रकारिता का मूल मंत्र रहा है-सत्यापन, संतुलन और संदर्भ। खबर छापने से पहले स्रोत की पुष्टि, दोनों पक्षों की राय और तथ्यों की जांच अनिवार्य मानी जाती थी। डिजिटल युग में भी यही सिद्धांत प्रासंगिक हैं। फर्क केवल माध्यम का है, मूल मूल्य का नहीं। लेकिन मीडिया भी दबाव में है। आर्थिक मॉडल बदल रहे हैं। विज्ञापन डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। प्रतिस्पर्धा तीव्र है। ऐसे में कई बार गति को प्राथमिकता मिलती है, गहराई पीछे छूट जाती है।

यही वह मोड़ है जहां आत्ममंथन जरूरी है। क्या हम खबर दे रहे हैं या केवल सामग्री? क्या हम सूचना को संदर्भ सहित प्रस्तुत कर रहे हैं या केवल हेडलाइन पर निर्भर हैं? सरकारों ने भी डिजिटल नियमन की दिशा में कदम उठाए हैं। कई देशों में सोशल मीडिया कंपनियों से जवाबदेही तय करने की कोशिश हो रही है।

भारत में भी आईटी नियमों और फेक न्यूज पर नियंत्रण की चर्चा चलती रहती है। लेकिन कानून अकेला समाधान नहीं है। यदि नागरिक स्वयं सजग न हों, तो कोई भी नियम पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल साक्षरता इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्कूलों और कॉलेजों में केवल तकनीक का उपयोग सिखाना पर्याप्त नहीं है। सूचना का मूल्यांकन कैसे करें, यह भी सिखाया जाना चाहिए। किसी भी संदेश को साझा करने से पहले स्रोत की जांच, तारीख की पुष्टि और संदर्भ समझना जरूरी है। यह जिम्मेदारी हर उपयोगकर्ता की है। डिजिटल युग का एक सकारात्मक पहलू भी है-पारदर्शिता। अब सत्ता या संस्थान पूरी तरह से सूचना छिपा नहीं सकते। नागरिक पत्रकारिता ने कई बार महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं।

लेकिन पारदर्शिता तभी प्रभावी होगी जब वह तथ्यों पर आधारित हो। यदि आरोप बिना प्रमाण के लगाए जाएंगे, तो विश्वास घटेगा। यह भी सच है कि सूचना का अत्यधिक प्रवाह मानसिक थकान पैदा करता है। हर घंटे नई खबर, नई बहस और नया विवाद सामने आता है। नागरिकों को तय करना होगा कि वे किस पर ध्यान दें और किसे नजरअंदाज करें। गुणवत्ता की पहचान करना भी एक कौशल है।

डिजिटल युग में पत्रकारिता की भूमिका खत्म नहीं हुई, बल्कि और महत्वपूर्ण हो गई है। जब भ्रम अधिक हो, तब स्पष्टता की जरूरत बढ़ती है। जब शोर बढ़े, तब संतुलित आवाज की आवश्यकता होती है। एक जिम्मेदार अखबार या मंच का दायित्व है कि वह केवल खबर न दे, बल्कि संदर्भ भी दे, विश्लेषण भी दे और समाज को सोचने का अवसर भी दे।

सूचना शक्ति है। लेकिन बिना सत्यापन के सूचना भ्रम भी बन सकती है। डिजिटल दुनिया में हर क्लिक का असर है। इसलिए जरूरी है कि हम तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें।

आज आवश्यकता है तीन बातों की- सत्यापन, संतुलन और सजग नागरिकता। यदि ये तीन मजबूत होंगे, तो डिजिटल युग अवसर बनेगा, संकट नहीं। डिजिटल क्रांति को रोकना संभव नहीं, और न ही आवश्यक है। आवश्यक है उसे दिशा देना।

सवाल यह नहीं कि खबर कितनी तेज है। सवाल यह है कि खबर कितनी सच्ची है। और यही तय करेगा कि डिजिटल युग लोकतंत्र को मजबूत करेगा या उसे भ्रम के जाल में उलझा देगा।

विकास की रफ्तार और जमीनी हकीकत

सुनिए सरकार

प्रीति खण्डूरी
एग्जीक्यूटिव एडिटर (सुनिए सरकार)

भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लगातार भारत की विकास दर को मजबूत बता रही हैं।

बुनियादी ढांचे में निवेश, डिजिटल भुगतान व्यवस्था, स्टार्टअप इकोसिस्टम और विनिर्माण क्षेत्र में नई पहलें-ये सभी संकेत देते हैं कि देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विकास समान रूप से महसूस भी हो रहा है? सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग, सेमीकंडक्टर नीति, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) और हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश-ये सब दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती की दिशा में कदम हैं। विदेशी निवेश भी लगातार आ रहा है। भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विकास का दूसरा पहलू भी है। महंगाई, बेरोजगारी और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति जैसे मुद्दे जमीनी चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय स्थिरता और बाजार प्रतिस्पर्धा की चुनौती झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय वृद्धि की गति शहरी क्षेत्रों से अलग दिखाई देती है।

भारत की आर्थिक कहानी दो स्तरों पर चल रही है-एक वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास की कहानी, और दूसरी घरेलू स्तर पर संतुलन की जरूरत। असली सफलता तब मानी जाएगी जब विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

आर्थिक वृद्धि तभी स्थायी होती है जब उसमें समावेशिता हो। नीति निर्माताओं के सामने चुनौती है कि वे तेज विकास और सामाजिक संतुलन के बीच तालमेल बनाए रखें। भारत के पास युवा शक्ति, डिजिटल आधार और विशाल बाजार है। यदि रोजगार सृजन और आय असमानता पर समान ध्यान दिया जाए, तो देश की आर्थिक यात्रा और मजबूत हो सकती है।

त्वचा रोग विशेषज्ञ से सीधी बात

होली के रंग में त्वचा की रंगत का रखें ध्यान

'मस्ती में न भूलें सुरक्षा, होली खेलें पर सुरक्षित खेलें'

देहरादून (सुनिए सरकार ब्यूरो)। होली का त्योहार भारत की सांस्कृतिक पहचान का रंगीन प्रतीक है। यह सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि मेल-मिलाप, भाईचारे,उल्लास और सामूहिक आनंद का अवसर है।

लेकिन बदलते समय के साथ होली के रंग भी बदल गए हैं। जहां पहले फूलों और प्राकृतिक पदार्थों से रंग तैयार होते थे, वहीं अब बाजार में उपलब्ध कई रंग केमिकल तत्वों से बने होते हैं।

त्वचा रोग विशेषज्ञों के अनुसार, होली के बाद मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिलती है- खुजली, रैशेज, एलर्जी, फंगल संक्रमण, बालों का झड़ना और यहां तक कि आंखों की जलन जैसी समस्याएं आम हैं।

सुनिए डॉक्टर साहब

इन्हीं विषयों पर हमने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. भव्या सहगल (एमडी, डर्मेटोलॉजी) से विस्तार से बातचीत की।

सवाल: होली के रंग त्वचा के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं?

डॉक्टर: आजकल बाजार में मिलने वाले कई रंगों में औद्योगिक डाई, सीसा (Lead), क्रोमियम, कॉपर सल्फेट और अन्य भारी धातुएं मिलाई जाती हैं। ये तत्व त्वचा की ऊपरी परत (एपिडर्मिस) को नुकसान पहुंचाते हैं।

त्वचा की संरचना तीन परतों से बनी होती है- एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। जब रासायनिक रंग एपिडर्मिस को प्रभावित करते हैं, तो त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ जाती है। इससे एलर्जी, सूजन, लालिमा और जलन आदि की समस्या हो सकती है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ मामलों में 'कॉन्टैक्ट डर्मेटाइ-टस' विकसित हो जाता है, जिसमें त्वचा पर छोटे-छोटे दाने और तीव्र खुजली होती है।

सवाल: क्या हर व्यक्ति को समान जोखिम होता है?

डॉक्टर: नहीं। जिन लोगों की त्वचा संवेदनशील (Sensitive Skin) होती है, या जिन्हें पहले से एलर्जी, एक्जिमा, सोरायसिस, मुंहासे या फंगल संक्रमण है, उन्हें अधिक खतरा रहता है।

बच्चों की त्वचा पतली और कोमल होती है, इसलिए वे अधिक प्रभावित होते हैं। बुजुर्गों की त्वचा में भी प्राकृतिक तेल कम हो जाता है, जिससे जलन की संभावना बढ़ जाती है।

सवाल: होली खेलने से पहले त्वचा की तैयारी कैसे करें?

डॉक्टर: यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है।

✔ **मॉइस्चराइजेशन:** त्वचा पर मोटी परत में मॉइस्चराइजर या नारियल तेल लगाएं। यह एक 'बैरियर' की तरह काम करता है और रंग को सीधे त्वचा में प्रवेश करने से रोकता है।

✔ **सनस्क्रीन**

दिन में बाहर होली खेल रहे हैं, तो SPF30 या उससे अधिक सनस्क्रीन लगाएं। धूप और केमिकल रंग का संयोजन त्वचा को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है।

✔ **फुल स्लीव कपड़े**

पूरे बाजू के कपड़े, फुल पैंट या ट्रैक सूट पहनें। त्वचा का कम हिस्सा खुला रहेगा।

✔ **बालों की सुरक्षा**

बालों में सरसों या नारियल तेल लगाएं। इससे रंग बालों में चिपकता नहीं और आसानी से निकल जाता है।

✔ **नाखूनों की सुरक्षा**

नाखून छोटे रखें और उन पर नेल पॉलिश लगा लें ताकि रंग अंदर जमा न हो।

सवाल: क्या हर्बल या ऑर्गेनिक रंग पूरी तरह सुरक्षित हैं?

डॉक्टर: हर्बल रंग अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं, लेकिन 100 प्रतिशत सुरक्षित कहना गलत होगा। बाजार में कई उत्पाद 'ऑर्गेनिक' नाम से बेचे जाते हैं, पर उनमें भी मिलावट हो सकती है।

बेहतर विकल्प यह है कि घर पर फूलों से रंग तैयार किए जाएं। गेंदे के फूल से पीला, चुकंदर से गुलाबी,पालक से हरा रंग।

सवाल: होली के बाद रंग हटाने का सही तरीका क्या है?

डॉक्टर: लोग अक्सर रंग हटाने के लिए जोर-जोर से रगड़ते हैं, जो त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाता है। सही तरीका ये है कि पहले सादे पानी से रंग ढीला करें। हल्के क्लेंजर का प्रयोग करें। बेसन और दही का लेप उपयोग कर सकते हैं। गुनगुने पानी से स्नान करें और बाद में मॉइस्चराइजर अवश्य लगाएं। बालों के लिए माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर का उपयोग करें।

सवाल: किन लक्षणों को गंभीर मानकर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

डॉक्टर: त्वचा पर तीव्र सूजन, फफोले, स-ांस लेने में कठिनाई (एलर्जिक रिएक्शन), लगातार खुजली, आंखों में जलन या धुंधलापन। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लें।

सवाल: क्या होली के बाद मुंहासे बढ़ सकते हैं?

डॉक्टर: जी हां। रंगों में मौजूद केमिकल और धूल त्वचा के रोमछिद्र (पोर) बंद कर देते हैं। इससे एक्ने या पिंपल्स बढ़ सकते हैं। तेल लगाना जरूरी है, लेकिन अत्यधिक तेल लगाने से भी पोर बंद हो सकते हैं। संतुलन जरूरी है।

सवाल: क्या पानी वाली गीली होली ज्यादा सुरक्षित है?

डॉक्टर: जरूरी नहीं। गीले रंगों में भी केमिकल हो सकते हैं। गंदा पानी त्वचा संक्रमण का कारण बन सकता है।

सवाल: बच्चों के लिए क्या विशेष सावधानी रखें?

डॉक्टर: बच्चों को केवल सुरक्षित, हर्बल रंगों से ही खेलने दें। आंखों और मुंह के आसपास रंग लगाने से बचें। होली के बाद तुरंत स्नान कराएं।

सवाल: क्या खानपान का असर पड़ता है?

डॉक्टर: जी हां। पानी अधिक पिएं। फल और सब्जियां लें। तला-भुना कम खाएं। हाइड्रेशन त्वचा की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।

ये सावधानियां हैं जरूरी

- होली खेलने से पहले त्वचा पर तेल या मॉइस्चराइजर की मोटी परत
- धूप में निकलें तो सनस्क्रीन लगाएं
- पूरे बाजू के कपड़े पहनें
- बालों में तेल लगाएं
- केमिकल रंगों से बचें, हर्बल रंग अपनाएं
- रंग हटाने के लिए त्वचा को जोर से न रगड़ें
- किसी भी गंभीर रिएक्शन पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

Dr Bhavya Sangal
MBBS, MD (Dermatology, venereology and Leprosy), DNB
Assistant professor
Department of Dermatology
Government Doon Medical College

डॉक्टर का सेफ होली का संदेश, होली हेल्थ चेकलिस्ट

'होली के त्योहार में त्वचा की सुरक्षा को नजरअंदाज न करें। थोड़ी तैयारी और थोड़ी सावधानी आपको त्योहार के बाद त्वचा संबंधी समस्याओं से बचा सकती है। इसलिए आर्गेनिक रंगों का ही प्रयोग करें। अगर त्वचा पर तीव्र सूजन, फफोले, सांस लेने में कठिनाई, लगातार खुजली, आंखों में जलन या धुंधलापन महसूस करें, तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें।

✔ पहले तेल/मॉइस्चराइज़र
✔ सनस्क्रीन
✔ फुल कपड़े
✔ हर्बल रंग
✔ हल्का क्लेंजर
✔ मॉइस्चराइज़र पोस्ट-होली

होली का रंग चेहरे पर मुस्कान लाए, त्वचा पर परेशानी नहीं। इसलिए रंग खेलिए, पर समझदारी के साथ।

रंग, राशि और ग्रहों की चाल: होली सिर्फ रंग नहीं, ऊर्जा का संसार है

देहरादून (सुनिए सरकार ब्यूरो)। होली को केवल रंगों का उत्सव समझना अधूरा दृष्टिकोण है। भारतीय ज्योतिष और परंपरा में यह पर्व ऋतु परिवर्तन, नकारात्मक ऊर्जा के दहन और नए सौर चक्र की तैयारी का प्रतीक माना जाता है।

होली पर ग्रहों की क्या स्थिति रहती है? राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कुछ विशेष उपाय करने चाहिए? इन सभी प्रश्नों पर हमने ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद पोखरियाल जी से बातचीत की।

ज्योतिषाचार्य से विशेष बातचीत

पंडित विनोद पोखरियाल
रत्न शास्त्री ज्योतिषविभूषण सम्मानित, उत्तराखंड

सवाल: ज्योतिष के अनुसार होली का क्या महत्व है?

ज्योतिषाचार्य: होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। पूर्णिमा का चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। जब पूर्णिमा और अग्नि तत्व (होलिका दहन) का संगम होता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का संकेत देता है।

यह समय सर्दी से गर्मी की ओर संक्रमण का भी है। सूर्य की ऊर्जा बढ़ने लगती है और प्रकृति में परिवर्तन शुरू होता है। ज्योतिष में इसे 'ऊर्जा शुद्धि' का काल माना जाता है।

सवाल: इस वर्ष ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव रहेगा?

ज्योतिषाचार्य: फाल्गुन पूर्णिमा के आसपास सूर्य मीन राशि में और चंद्रमा कन्या या तुला राशि में स्थित हो सकता है। यह भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक चिंतन का संकेत देता है। अगर मंगल सक्रिय हो, तो ऊर्जा और उत्साह अधिक रहेगा। लेकिन संयम जरूरी है।

सवाल: होलिका दहन का आध्यात्मिक महत्व क्या है?

ज्योतिषाचार्य: होलिका दहन अहंकार, नकारात्मकता और पुराने कष्टों के दहन का प्रतीक है। इस दिन लोग गेहूं की बालियां, नारियल या सूखे गोबर के उपले अग्नि में अर्पित करते हैं।

यह प्रतीकात्मक रूप से बुराइयों को छोड़ने का संदेश देता है। ज्योतिष में अग्नि शुद्धिकरण का माध्यम है।

सवाल: क्या होली पर कोई विशेष उपाय करने चाहिए?

ज्योतिषाचार्य:

- होलिका दहन के समय परिक्रमा करें
- चंद्रमा को अर्घ्य दें
- घर में गुलाल या केसर का तिलक लगाएं
- जरूरतमंदों को वस्त्र या मिठाई दान करें
- घर में सकारात्मक मंत्रों का जाप करें

यह उपाय मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं।

सवाल: क्या रंगों का भी ज्योतिष में महत्व है?

ज्योतिषाचार्य: बिलकुल।

- लाल- मंगल और ऊर्जा
- पीला- गुरु और ज्ञान
- हरा- बुध और संतुलन
- नीला- शनि और स्थिरता
- गुलाबी- प्रेम और सौहार्द

होली पर रंगों का प्रयोग केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक ऊर्जा विनिमय है।

सवाल: क्या होली के दिन कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए?

ज्योतिषाचार्य: पूर्णिमा के दिन मन संवेदनशील होता है। विवाद, क्रोध या नशे से बचना चाहिए। होली आनंद का पर्व है, अराजकता का नहीं।

होली पर राशियों पर अलग-अलग प्रभाव

मष (Aries): ऊजा चरम पर रहगा। उत्साह में जल्दबाज़ी से बचें। होली पर लाल या गुलाबी रंग शुभ रहेगा।

वृषभ (Taurus): परिवार और मित्रों के साथ समय सुखद रहेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। हल्का हरा रंग शुभ।

मिथुन (Gemini): नए संपर्क बन सकते हैं। संवाद में मधुरता रखें। पीला रंग सौभाग्य बढ़ाएगा।

कर्क (Cancer): भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव। विवाद से बचें। सफेद या क्रीम रंग मानसिक शांति देगा।

सिंह (Leo): सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग। उत्सव का केंद्र बन सकते हैं। केसरिया या सुनहरा रंग अनुकूल।

कन्या (Virgo): स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खानपान नियंत्रित रखें। हरा या हल्का पीला रंग शुभ।

तुला (Libra): सबधा म सामजस्य का समय। मित्रों के साथ आनंददायक दिन। गुलाबी या आसमानी रंग लाभकारी।

वृश्चिक (Scorpio): ऊर्जा प्रबल रहेगी, पर क्रोध से बचें। गहरा लाल या मरून रंग अनुकूल।

धनु (Sagittarius): यात्रा या नए अवसर मिल सकते हैं। पीला या केसरिया रंग शुभ संकेत देगा।

मकर (Capricorn): काम और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन रखें। नीला या धूसर रंग सकारात्मक ऊर्जा देगा।

कुम्भ (Aquarius): रचनात्मकता बढ़ेगी। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे। नीला या बैंगनी रंग अनुकूल।

मीन (Pisces): आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। होली पर संयम और सकारात्मक सोच रखें। हल्का पीला या गुलाबी रंग शुभ रहेगा।

निष्कर्ष

होली केवल रंगों का खेल नहीं, यह ऊर्जा का नवीनीकरण है। होलिका दहन हमें सिखाता है कि अहंकार जलाइए, संबंध बचाइए। रंगों से जीवन में खुशियां भरिए, लेकिन मर्यादा और सकारात्मकता के साथ।

Suniye Sarker 2nd March 2026_Layout 1 3/2/2026 9:48 PM Page 6

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी की आहट?

दुनिया में महंगाई, ब्याज दरें और भू-राजनीतिक तनाव से बढ़ी चिंता

वाशिंगटन/ब्रुसेल्स/बीजिंग/नई दिल्ली (सुनिए सरकार ब्यूरो)। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक कठिन संतुलन के दौर से गुजर रही है।

कोविड महामारी के बाद उबरती अर्थव्यवस्था, फिर रूस-यूक्रेन युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला संकट, और उसके बाद बढ़ती महंगाई-इन सबने वैश्विक आर्थिक ढांचे को झकझोर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक ने हालिया रिपोर्टों में चेतावनी दी है कि वैश्विक विकास दर धीमी रह सकती है।

कई विकसित देशों में विकास दर 2 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है, जबकि कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं।

महंगाई और ब्याज दरों का चक्र: महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और अन्य केंद्रीय बैंकों ने पिछले दो वर्षों में ब्याज दरें बढ़ाई हैं।

ब्याज दरें बढ़ने से ऋण महंगे हुए और निवेश धीमा पड़ा है। जबकि रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुए। स्टार्टअप फंडिंग में गिरावट आई है।

हालांकि कुछ देशों में महंगाई दर अब घटने लगी है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती बनी हुई है।

चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार: चीन, जो लंबे समय तक वैश्विक विकास का इंजन माना जाता था, अब धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। रियल एस्टेट संकट, निर्यात में गिरावट और कमजोर घरेलू मांग ने वैश्विक बाजारों पर भी असर डाला है।

यूरोप की चुनौती: यूरोप ने रूस से गैस आयात घटाकर ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाई है, लेकिन ऊंची ऊर्जा कीमतों ने उद्योगों पर दबाव डाला। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों में औद्योगिक उत्पादन प्रभावित।

अमेरिका की स्थिति: अमेरिका में रोजगार के आंकड़े मजबूत रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता कर्ज बढ़ा है। ब्याज दरें उच्च स्तर पर हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है।

भारत का स्थान: भारत को वैश्विक परिदृश्य में अपेक्षाकृत स्थिर अर्थव्यवस्था माना जा रहा है। जीडीपी वृद्धि दर सकारात्मक, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जारी और डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन भारत भी वैश्विक मांग में गिरावट, कच्चे तेल की कीमत और निर्यात पर निर्भरता से पूरी तरह अलग नहीं है।

विकासशील देशों पर असर: अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों पर डॉलर मजबूत होने का दबाव, कर्ज संकट, खाद्य महंगाई की स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण है।

वैश्विक मंदी की आशंका: विश्लेषकों के अनुसार पूर्ण वैश्विक मंदी की संभावना कम है, लेकिन विकास दर धीमी, असमान वृद्धि, क्षेत्रीय अस्थिरता, दुनिया 'लो ग्रोथ-हाई अनिश्चितता' के दौर में है।

सुनिए सरकार-सिस्टम से सवाल

- क्या वैश्विक संस्थाएं आर्थिक स्थिरता के लिए संयुक्त रणनीति बना पा रही हैं?
- क्या केंद्रीय बैंकों की नीतियां आम लोगों पर ज्यादा बोझ डाल रही हैं?
- क्या विकासशील देशों को कर्ज राहत के ठोस उपाय मिलेंगे?
- क्या वैश्विक व्यापार व्यवस्था नए संतुलन की ओर बढ़ रही है?

निष्कर्ष

दुनिया फिलहाल किसी एक बड़े संकट में नहीं, बल्कि कई छोटे संकटों के संयुक्त दबाव में है। महंगाई, युद्ध, ऊर्जा, कर्ज, और राजनीतिक अस्थिरता-ये सभी कारक मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक संवेदनशील मोड़ पर ले आए हैं। यह समय घबराने का नहीं, बल्कि संतुलन, समन्वय और जिम्मेदार नीति का है। अगर विश्व नेतृत्व ने सही कदम उठाए, तो मंदी की आशंका टल सकती है। लेकिन यदि समन्वय की कमी रही – तो आर्थिक झटका व्यापक हो सकता है।

यूरोप की अर्थव्यवस्था दबाव में: ऊर्जा संकट, महंगाई और युद्ध की कीमत

जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की सुस्ती का वैश्विक असर

ब्रुसेल्स / बर्लिन / पेरिस / लंदन (सुनिए सरकार ब्यूरो)। यूरोप एक बार फिर आर्थिक अनिश्चितता के दौर में खड़ा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से ऊर्जा आपूर्ति, गैस कीमतों, औद्योगिक उत्पादन और महंगाई ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बनाए रखा है। हाल के आर्थिक आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि जर्मनी और फ्रांस जैसे प्रमुख देश विकास दर में सुस्ती का सामना कर रहे हैं।

यूरोपीय आयोग और यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) ने पिछले महीनों में कई बार ब्याज दरों को लेकर सख्त संकेत दिए हैं। उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना है, लेकिन ऊंची ब्याज दरें निवेश और उद्योग पर अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं।

जर्मनी: यूरोप का इंजन धीमा क्यों? जर्मनी को यूरोप की औद्योगिक शक्ति कहा जाता है। लेकिन हालिया महीनों में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में गिरावट, ऊर्जा लागत में वृद्धि और निर्यात में कमी ने उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। रूस से गैस आपूर्ति घटने के बाद जर्मनी को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर होना पड़ा, जिससे उत्पादन लागत बढ़ी। ऑटोमोबाइल और मशीनरी उद्योग पर इसका सीधा असर पड़ा है।

फ्रांस: सामाजिक दबाव व आर्थिक असंतुलन- फ्रांस में पेंशन सुधार और श्रम नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक आंदोलन ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। फ्रांस की सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सब्सिडी और राहत पैकेज दिए, लेकिन इससे राजकोषीय घाटा बढ़ा है।

ब्रिटेन: ब्रेक्जिट के बाद की चुनौती- ब्रिटेन पहले ही ब्रेक्जिट के बाद व्यापार पुनर्गठन से गुजर रहा है। ऊर्जा कीमतों और वैश्विक मंदी की आशंकाओं ने ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को और जटिल बना दिया है। पाउंड की अस्थिरता, उपभोक्ता खर्च में गिरावट, बैंकिंग सेक्टर पर दबाव- ये संकेत बाजार को सावधान कर रहे हैं।

ऊर्जा संकट का असर: रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद यूरोप ने रूसी गैस पर निर्भरता कम की, लेकिन वैकल्पिक स्रोत महंगे साबित हुए। LNG आयात, हरित ऊर्जा संक्रमण और ऊर्जा सब्सिडी पर भारी खर्च ने बजट पर दबाव बढ़ाया। ऊर्जा लागत बढ़ने से उद्योग महंगे हुए। उपभोक्ता बिल, उत्पादन लागत, महंगाई और ब्याज दर बढ़ी। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाईं। इससे होम लोन महंगे हुए और निवेश घटा। छोटे उद्योग प्रभावित हुए। महंगाई और मंदी के बीच संतुलन बनाना ECB के लिए चुनौती बना हुआ है।

वैश्विक असर: यूरोप वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र है। यदि यूरोप की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो एशियाई निर्यात प्रभावित होता है।

भारत पर संभावित प्रभाव: ऊर्जा बाजार के अस्थिर और वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट का भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ सकता है, खासकर निर्यात और आईटी सेवाओं के क्षेत्र में। यूरोप भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर यूरोप में मांग घटती है तो भारतीय निर्यात कम हो सकता है। आईटी और फार्मा सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। मुद्रा विनिमय दर में अस्थिरता आ सकती है, लेकिन दूसरी ओर ऊर्जा और रक्षा सहयोग में अवसर भी खुल सकते हैं।

सुनिए सरकार – सिस्टम से सवाल

- क्या भारत को यूरोप की सुस्ती से बचाव के लिए निर्यात विविधीकरण करना चाहिए?
- क्या अंतरराष्ट्रीय सहयोग से मंदी के खतरे को कम किया जा सकता है?

नेपाल चुनाव 2026: हिमालय के पार बदलती राजनीति और भारत पर उसका असर

काठमांडू / नई दिल्ली / बीजिंग (सुनिए सरकार ब्यूरो)। नेपाल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। हाल के हफ्तों में काठमांडू में राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। संसद के भीतर गठबंधन समीकरणों, नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों और आने वाले चुनावी परिदृश्य ने दक्षिण एशिया की कूटनीति को भी सक्रिय कर दिया है।

नेपाल का हर चुनाव केवल आंतरिक सत्ता परिवर्तन नहीं होता। उसका सीधा असर भारत-नेपाल संबंधों, चीन की क्षेत्रीय रणनीति, सीमाई व्यापार, जल संसाधन समझौतों और सुरक्षा समन्वय पर पड़ता है।

नेपाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति: नेपाल पिछले एक दशक से गठबंधन राजनीति के दौर से गुजर रहा है। कम्युनिस्ट धड़ा, नेपाली कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच बार-बार बदलते समीकरण ने स्थिर सरकार बनाना चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों में: संसद में विश्वास मत को लेकर चर्चा, गठबंधन पुनर्गठन की अटकलें, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद को लेकर अंदरूनी मतभेद हमेशा से नेपाल में जारी रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता अभी भी नाजुक है।

भारत-नेपाल संबंध: ऐतिहासिक गहराई से अगर देखा जाए तो भारत और नेपाल के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक भी हैं। भारत-नेपाल के बीच खुली सीमा व्यवस्था, लाखों नेपाली नागरिक भारत में कार्यरत, धार्मिक व पारिवारिक संबंध और रक्षा सहयोग है लेकिन समय-समय पर सीमा विवाद, नक्शा विवाद और राजनीतिक बयानबाजी से रिश्तों में तनाव भी आया है।

चीन का बढ़ता प्रभाव: पिछले कुछ वर्षों में चीन ने नेपाल में बुनियादी ढांचे, सड़क, ऊर्जा और निवेश परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाई है। जैसे-बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), हाइड्रोपावर परियोजनाएं, कनेक्टिविटी समझौते। चीन नेपाल को दक्षिण एशिया में रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। भारत के लिए नेपाल के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।

अमेरिका-चीन टकराव: व्यापार, टेक्नोलॉजी और शक्ति संतुलन की नई लड़ाई

दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती दूरी का असर भारत पर कितना?

वाशिंगटन/बीजिंग/जिनेवा/नई दिल्ली (सुनिए सरकार ब्यूरो)। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं-अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने-सामने हैं। यह टकराव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।

इसमें टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), रक्षा सहयोग, इंडो-पैसिफिक रणनीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सब शामिल हैं।

पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने चीन की कई टेक कंपनियों पर अतिरिक्त निर्यात नियंत्रण और प्रतिबंध लगाए हैं। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी कंपनियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खनिज निर्यात पर सख्ती दिखाई है। इस बीच विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भी दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस हुई। यह केवल आर्थिक विवाद नहीं है। यह वैश्विक नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा है।

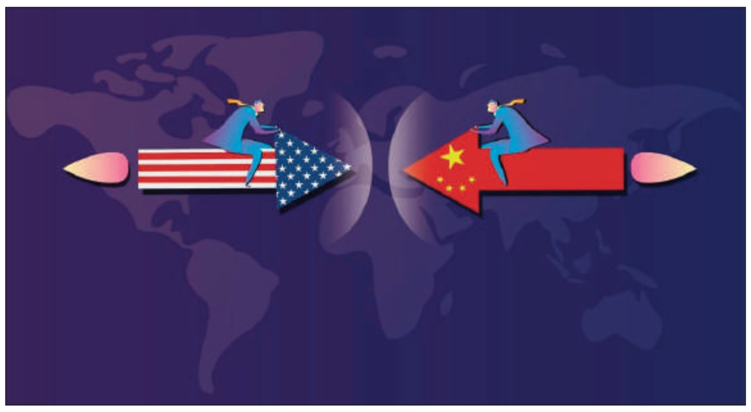

टकराव की ताजा वजह क्या?

हाल के सप्ताहों में अमेरिका ने उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई उपकरणों के निर्यात पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाए। चीन ने गैलियम और जर्मेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों के निर्यात नियंत्रण को सख्त किया। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधि बढ़ी। ताइवान मुद्दे पर बयानबाजी तेज हुई। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का मामला है। जबकि चीन का जवाब था कि यह 'आर्थिक आक्रामकता' है।

टेक्नोलॉजी वॉर-असली जंग

यह लड़ाई सबसे ज्यादा टेक सेक्टर में दिख रही है।

सेमीकंडक्टर: उन्नत चिप्स आधुनिक हथियार, एआई सस्टम और सुपरकंप्यूटर का आधार हैं। अमेरिका चाहता है कि चीन इन तक आसानी से पहुंच न बना सके। चीन अपने घरेलू चिप निर्माण को तेजी से बढ़ा रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: एआई अगली औद्योगिक क्रांति माना जा रहा है। जो देश एआई में आगे होगा, वह आर्थिक और सैन्य दोनों रूप से मजबूत होगा।

5G और संचार नेटवर्क: हुवावे और अन्य चीनी कंपनियों पर पहले से ही कई देशों में प्रतिबंध हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर: दोनों देशों की जीडीपी मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था का लगभग 40 फीसदी हिस्सा बनाती है। यदि दोनों के बीच टकराव बढ़ता है तो सप्लाई चेन बाधित, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद महंगे और ऊर्जा व लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ सकती है। ऐसे में यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत जैसे देशों को संतुलन साधना होगा।

भारत के लिए अवसर और चुनौती: भारत इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उसके पास चीन से हटती सप्लाई चेन का विकल्प बनना, सेमीकंडक्टर निर्माण निवेश आकर्षित करना और इंडो-पैसिफिक में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का अवसर है।

हालांकि चुनौती भी कम नहीं है। चीन भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सीमा तनाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अमेरिका से संबंध मजबूत, पर रणनीतिक स्वतंत्रता भी जरूरी है।

भारत की विदेश नीति 'रणनीतिक स्वायत्तता' पर आधारित है। लेकिन वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच यह संतुलन कठिन होता जा रहा है।

WTO और नियम आधारित व्यवस्था: विश्व व्यापार संगठन में चीन और अमेरिका के बीच कई विवाद लंबित हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या WTO अब भी उतना प्रभावी है जितना पहले था? विशेषज्ञों का मानना है कि बहुपक्षीय व्यवस्था कमजोर हुई है। द्विपक्षीय समझौते बढ़े हैं। व्यापार अब राजनीतिक हथियार बन गया है।

इंडो-पैसिफिक रणनीति: अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का 'क्वाड' समूह सक्रिय है। चीन इसे अपने खिलाफ रणनीतिक घेराबंदी मानता है।

दक्षिण चीन सागर में गतिविधियां बढ़ी हैं। ताइवान मुद्दा संवेदनशील बना हुआ है।

अगर टकराव बढ़ा तो क्या?: विश्लेषक इसे तीन संभावित परिदृश्यों में देख रहे हैं-सीमित आर्थिक टकराव जारी रहेगा, टेक सेक्टर पूरी तरह दो खेमों में बंट सकता है और सैन्य तनाव की आशंका (कम संभावना, पर जोखिम मौजूद) है।

बड़ा सवाल: क्या यह नया शीत युद्ध है?: कई विश्लेषक इसे 'नया शीत युद्ध' कहते हैं। लेकिन फर्क यह है कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं गहराई से जुड़ी हैं।

पूर्ण अलगाव संभव नहीं है। प्रतिस्पर्धा और सहयोग साथ-साथ चल रहे हैं।

मीडिया और सूचना युद्ध: दोनों देशों में सूचना नियंत्रण और प्रचार की रणनीति मजबूत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस संघर्ष का नया मैदान बन गए हैं। ऐसे में भारत को सजग, संतुलित और रणनीतिक रहना होगा।

> **सुनिए सरकार सिस्टम से सवाल**
> - क्या भारत इस टकराव में अवसर को रणनीति में बदल पाएगा?
> - क्या वैश्विक व्यापार फिर से नियम आधारित बनेगा?
> - क्या टेक्नोलॉजी दो धड़ों में बंट जाएगी?
> - क्या वैश्विक संस्थाएं इस टकराव को संतुलित कर पाएंगी?

वैश्विक ऊर्जा संकट: तेल, गैस और भू-राजनीति की नई जंग

कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, ओपेक प्लस की रणनीति और भारत पर सीधा असर

रियाद / वियना / वाशिंगटन / नई दिल्ली (सुनिए सरकार ब्यूरो)। दुनिया एक बार फिर ऊर्जा अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर रही है। मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध की लंबी छाया, ओपेक प्लस की उत्पादन नीति और अमेरिका की रणनीतिक ऊर्जा चालों ने वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर बना दिया है।

पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) और ओपेक की मासिक रिपोर्टों में सप्लाई और डिमांड को लेकर अलग-अलग आकलन सामने आए हैं।

निवेशकों में असमंजस है कि क्या तेल 100 डॉलर के पार जाएगा, या वैश्विक मंदी कीमतों को नीचे धकेलेगी? ऊर्जा केवल आर्थिक विषय नहीं है। यह राजनीति, सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है।

हाल की प्रमुख घटनाएं: ओपेक प्लस देशों ने उत्पादन कटौती की नीति जारी रखी। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद उसका तेल निर्यात जारी रहा। अमेरिका ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) के उपयोग पर संकेत दिए। मध्य-पूर्व में अस्थिरता से आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच एशिया-विशेषकर भारत और चीन सबसे बड़े खरीदार बने हुए हैं।

ओपेक प्लस की भूमिका: ओपेक प्लस (OPEC+) में सऊदी अरब, रूस सहित प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं। इनका उद्देश्य है-उत्पादन को नियंत्रित कर कीमत स्थिर रखना। सऊदी अरब ने कई बार स्वैच्छिक उत्पादन कटौती की घोषणा की है। रूस ने भी पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद उत्पादन रणनीति में बदलाव किया है।

विश्लेषकों का कहना है कि सप्लाई कम कर कीमत को सहारा दिया जा रहा है। वैश्विक मांग कमजोर पड़ने के संकेत भी मौजूद हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध का असर: 2022 से जारी युद्ध ने ऊर्जा बाजार को पूरी तरह बदल दिया। यूरोप ने रूसी गैस पर अपनी निर्भरता घटाई। रूस ने एशियाई बाजारों की ओर रुख किया। एलएनजी (LNG) की मांग बढ़ी। ऊर्जा अब केवल व्यापार नहीं, रणनीतिक हथियार बन चुकी है।

अमेरिका की रणनीति: अमेरिका अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ा रहा है। रणनीतिक भंडार का उपयोग संतुलन के लिए करता है। सहयोगी देशों के साथ ऊर्जा साझेदारी मजबूत कर रहा है, लेकिन अमेरिकी ऊर्जा नीति पर घरेलू राजनीति का भी असर है। चुनावी सालों में पेट्रोल कीमतें बड़ा मुद्दा बन जाती हैं।

तेल कीमतें और वैश्विक महंगाई: तेल महंगा होगा तो परिवहन और खाद्य वस्तुएं महंगी होंगी। निर्माण लागत बढ़ेगी यानी तेल सीधे महंगाई को प्रभावित करता है। यूरोप पहले ही ऊर्जा की महंगाई से जूझ चुका है। अमेरिका में भी ईंधन कीमतें राजनीतिक मुद्दा बनती रही हैं।

भारत पर असर: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। सकारात्मक पक्ष ये है कि रूस से रियायती दर पर तेल खरीद, विविध स्रोतों से आयात, रणनीतिक भंडार नीति भारत ने अपनाई है। हालांकि भारत के लिए चुनौती भी कम नहीं है। रुपये पर दबाव, आयात बिल में वृद्धि का महंगाई पर असर पड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था ऊर्जा आयात पर निर्भर है। तेल महंगा हुआ तो चालू खाता घाटा बढ़ सकता है।

क्या नवीकरणीय ऊर्जा समाधान है?: ऊर्जा संकट ने दुनिया को सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन की ओर धकेला है। भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाई। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया, लेकिन संक्रमण तुरंत संभव नहीं। फिलहाल तेल और गैस की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

भू-राजनीति बनाम बाजार: ऊर्जा बाजार अब केवल मांग-सप्लाई से नहीं चलता। अब इसमें प्रतिबंध, सैन्य तनाव, गठबंधन राजनीति, समुद्री मार्गों की सुरक्षा आदि शामिल है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे मार्ग संवेदनशील बने हुए हैं।

आगे क्या?: विश्लेषकों के अनुसार तीन संभावनाएं हैं-सीमित उतार-चढ़ाव जारी रहेगा, मध्य-पूर्व तनाव बढ़ा तो कीमतों में उछाल, वैश्विक मंदी आई तो मांग घटेगी।

> **निष्कर्ष**
> ऊर्जा संकट केवल तेल का मामला नहीं है। यह भू-राजनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य की दिशा का सवाल है। दुनिया संक्रमण काल में है-जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा की ओर। लेकिन जब तक यह संक्रमण पूरा नहीं होता, तेल की हर हलचल दुनिया की राजनीति को प्रभावित करती रहेगी।

> **सुनिए सरकार सिस्टम से सवाल**
> - क्या भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी ला पाएगा?
> - क्या रणनीतिक भंडार नीति पर्याप्त है?
> - क्या नवीकरणीय ऊर्जा पर निवेश पर्याप्त है?
> - क्या वैश्विक संस्थाएं ऊर्जा स्थिरता में भूमिका निभा पा रही हैं?

सुनिए सरकार
सिस्टम से सीधा सवाल...
देहरादून, सोमवार, 02 मार्च 2026

मध्य-पूर्व संकट के बीच सबसे बड़ा संघर्ष

तेहरान/वाशिंगटन/जेरूसलम (सुनिए सरकार-फीचर डेस्क)। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सैन्य शक्ति और राजनीतिक स्थिरता के बीच की दूरी बेहद छोटी दिखती है और Operation Lion's Roar ने इसकी पुष्टि कर दी है।

28 फरवरी को इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त सेना ने ईरान पर एक बड़े पैमाने पर हमला चलाया, जिसको इज़रायली सरकार ने Operation Lion's Roar का नाम दिया। इस ऑपरेशन ने न केवल क्षेत्रीय राजनीति को बदल दिया है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा संतुलन पर भी गहरे असर डाले हैं।

कब और कैसे शुरू हुआ हमला

सुबह करीब 08:15 बजे (स्थानीय समय), इजराइल तथा अमेरिका द्वारा पूर्वनिर्धारित सामरिक हमलों की श्रृंखला ईरान के कई संवेदनशील सैन्य और सरकारी ठिकानों पर शुरू की गई, जिनमें रक्षा नियंत्रण केंद्र, मिसाइल डिपो, एयर डिफेंस सिस्टम और खुफिया नेटवर्क शामिल थे।

इजराइली रक्षा अधिकारियों के अनुसार, यह हमला 'तेहरान के आतंकवादी और सैन्य खतरे को रोका जाए' के उद्देश्य से चलाया गया था। हमले की शुरुआत के कुछ ही घंटे बाद, इजराइल के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। ये घटना दुनियाभर में सबसे बड़ी खबर बनी।

असर और परिणाम-युद्ध का मजबूत चरण: दुनिया भर के प्रमुख शहरों में हमला जैसे ही शुरू हुआ, धमाकों की आवाजें तेहरान में सुनाई दीं, सड़कें बंद कर दी गईं और आपातकालीन सूचना अलर्ट जारी किए गए। खबर लिखे जाने तक इन हमलों में 200 से ज्यादा मौतें और 750 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है।

नागरिकों और स्थानों का नुकसान हुआ है। विशेष रूप से दक्षिणी ईरान के एक स्कूल पर मिसाइल हमले के बाद 57 छात्रों की मौत और 45 घायल होने की रिपोर्टें भी आईं। इस घटना ने न केवल युद्ध की भयावहता को उजागर किया बल्कि मानवीय संकट को भी केंद्रित किया। तेहरान, अबू धाबी और अन्य खाड़ी

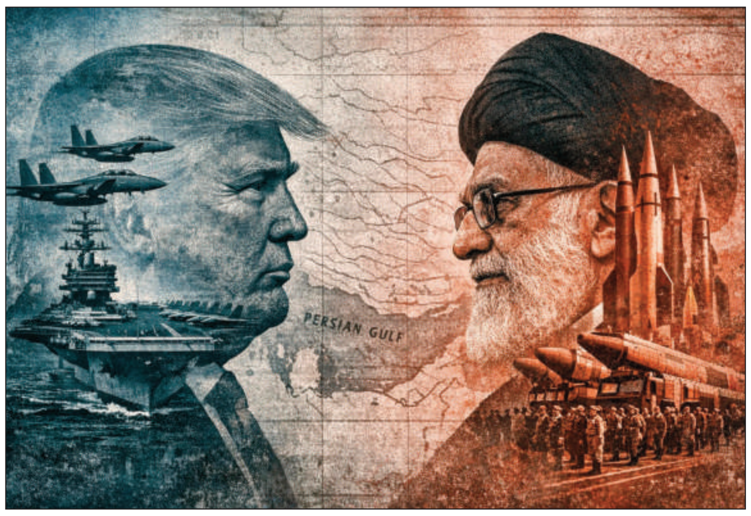

सुनिए सरकार-सिस्टम से सवाल

- क्या भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार की है?
- क्या खाड़ी क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षा पर स्पष्ट योजना है?
- क्या भारत शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा?
- क्या संसद में इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी?

शहरों में मिसाइल हमले, आग की लपटें, और धुएं के बादल बीच जनता भयभीत दिखी और स्थानीय नागरिक बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

वैश्विक प्रतिक्रियाएं-समर्थन और विरोध में उतरे दुनिया के देश:

रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'अप्रत्याशित और अनुचित सैन्य आक्रमण' करार दिया है, तथा तत्काल प्रभाव से हिंसा को रोकने और शांति वार्ता को प्राथमिकता देने की अपील की है।

रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यह हमला न सिर्फ स्थिरता को खतरे में डालता है, बल्कि मानवीय संकट के साथ आर्थिक नुकसान और दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए जोखिम भी पैदा करता है।

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी कड़े शब्दों में ईरानी मिसाइल हमलों को खाड़ी राष्ट्रों पर हमला बताया और संभावित गंभीर परिणामों की चेतावनी दे डाली।

इजराइल के भीतर राष्ट्रीय समर्थन इस ऑपरेशन के लिए उभरा, जिसमें विपक्षी नेताओं ने भी मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और खतरे को रोकने का पक्ष लिया।

राजनीतिक और कूटनीतिक पैमाना

इस संघर्ष की शुरुआत से पहले, अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी 2026 में कूटनीतिक वार्ता भी जारी थी।

जिसमें मिसाइल नियंत्रण और परमाणु वार्ता को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बातचीत के समापन के बाद दोनों पक्षों ने अंतिम रूप से सैन्य कदम उठाए।

मानवीय प्रभाव-आम नागरिकों पर असर: तेहरान, अबू धाबी और आसपास के इलाकों में बुनियादी संरचना पर विनाश का असर स्पष्ट है।

अस्पतालों में घायल लोग भर्ती हैं, स्कूलों में हड़कंप मचा है, सड़कें और बाजार अस्थायी रूप से बंद हैं, और कई परिवारों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। कई छोटे व्यापार, शैक्षणिक संस्थान और स्थानीय सेवाएं प्रभावित हुई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था संकट के दौर में है।

ईरान संकट: भारत के लिए खतरा या कूटनीतिक अवसर?

वैश्विक विश्लेषण

नई दिल्ली/ तेहरान/ वाशिंगटन/ जेरूसलम (सुनिए सरकार ब्यूरो)। मध्य-पूर्व में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को दुनिया सिर्फ एक और क्षेत्रीय युद्ध के रूप में देख रही है। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं है। यह ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, भारतीय प्रवासियों और रणनीतिक संतुलन की परीक्षा है। भारत सीधे युद्ध में नहीं है। लेकिन असर सीधे भारत तक आएगा।

तेल का झटका-पेट्रोल पंप से संसद तक: भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 80 फीसदी आयात करता है। ईरान भले अब भारत का प्रमुख सप्लायर न हो, लेकिन फारस की खाड़ी से गुजरने वाला Hormuz Strait भारत के लिए जीवन रेखा है। अगर खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल हमले बढ़ते हैं तो समुद्री मार्ग असुरक्षित होते हैं। बीमा प्रीमियम बढ़ता है और तेल टैंकरों की आवाजाही घटती है। तो भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा होगा। महंगाई बढ़ेगी। परिवहन लागत बढ़ेगी और आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा। सवाल ये भी है कि क्या भारत ने वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों और आपूर्ति मार्गों पर पर्याप्त तैयारी की है?

भारतीय नौसेना की भूमिका: मध्य-पूर्व संकट का दूसरा बड़ा पहलू है समुद्री सुरक्षा। भारतीय नौसेना पहले भी खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात रही है। अगर संघर्ष लंबा चलता है तो भारतीय जहाजों की एस्कॉर्ट जरूरत बढ़ेगी। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा चिंता बनेगी। भारतीय कंपनियों का निर्यात प्रभावित होगा।

भारत को एक साथ अमेरिका से रिश्ते संभालने हैं। इजराइल से रक्षा साझेदारी निभानी है। ईरान से चाबहार परियोजना जारी रखनी है। यह आसान संतुलन नहीं है।

कूटनीतिक संतुलन-न किसी के साथ पूरी तरह, न खिलाफ: भारत की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों में 'रणनीतिक स्वायत्तता' पर आधारित रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने यही रास्ता चुना था।

अब सवाल है कि क्या भारत ईरान और अमेरिका संघर्ष में भी वही संतुलन बनाए रख पाएगा? भारत के लिए तीन चुनौतियां हैं-अमेरिका के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी, इजराइल के साथ तकनीकी सहयोग और ईरान के साथ चाबहार और मध्य एशिया कनेक्टिविटी। अगर भारत खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़ा दिखता है, तो दूसरा पक्ष दूरी बना सकता है।

भारतीय प्रवासी-छुपा हुआ मानवीय संकट: खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। तनाव बढ़ने की स्थिति में एयरस्पेस बंद हो सकते हैं। वीजा/कामकाज प्रभावित हो सकता है। अचानक निकासी अभियान की जरूरत पड़ सकती है। भारत ने पहले भी 'ऑपरेशन गंगा' जैसे अभियान चलाए हैं। लेकिन क्या सरकार ने इस बार भी कोई आपात योजना तैयार रखी है?

शेयर बाजार और रुपया-अंतरराष्ट्रीय संकट का असर: शेयर बाजार में गिरावट, रुपया कमजोर, विदेशी निवेशकों की निकासी, सोना महंगा की आशंका। अगर तेल के दाम 10-15 फीसदी उछलते हैं, तो भारतीय बाजारों में झटका तय है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि भारत चुप रहे या सक्रिय भूमिका निभाए? क्या भारत मध्य-पूर्व में शांति प्रयासों की मध्यस्थता कर सकता है? क्या भारत वैश्विक मंच पर 'संतुलित शक्ति' बन सकता है? या फिर वह सिर्फ दर्शक बना रहेगा? भारत के पास अमेरिका से मजबूत रिश्ते, इजरायल से तकनीकी सहयोग और ईरान से संवाद का रास्ता है। ऐसे में भारत अगर चाहे तो सेतु बन सकता है, लेकिन इसके लिए साहस और कूटनीतिक सक्रियता चाहिए।

स्वामी एवं प्रकाशक अजय नौटियाल द्वारा मुद्रक पुनम सिंह, चारधाम प्रिंटिंग प्रेस, 53 डंगवाल मार्ग, चुक्खूवाला, देहरादून, उत्तराखंड-248001 द्वारा मुद्रित।
201, फर्स्ट फ्लोर, अपर राजीव नगर, धर्मपुर, देहरादून, उत्तराखंड-248001 से प्रकाशित। ईमेल- editor@suniyesarkar.com वेबसाइट- www.suniyesarkar.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी है। समस्त विवाद देहरादून न्यायालय के अधीन होंगे।